

दिनांक 10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

**भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात दावे एवं रोजगार परिणाम**

1612, श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्री जी स्पष्ट रूप से यह आश्वासन देते हैं कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात वृद्धि, मोबाइल फोन उत्पादन और सेमीकंडक्टर पहल से वादे किए अनुसार रोजगार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे या क्या सरकार उपलब्धियों को बढ़ा-चढ़ाकर बता रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) कतिपय राज्यों अथवा क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के अत्यधिक संकेन्द्रण को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ताकि पूरे भारत में समान आर्थिक लाभ और रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जा सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने निर्यात के लिए एप्पल जैसी विदेशी कंपनियों पर निर्भरता का आकलन किया है जिससे भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखला संबंधी कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो इसके लिए क्या उपशमन उपाय किए जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह पता लगाने के लिए कितने निगरानी और सूचना तंत्र मौजूद हैं कि निर्यात वृद्धि वास्तविक रोजगार, कौशल विकास और स्थानीय उद्योग के लाभों में परिवर्तित हो रही है और क्या ऐसी रिपोर्टें संसद में प्रस्तुत की जानी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री जितिन प्रसाद)**

(क) इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, निर्यात बढ़ाने, स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन के लिए, सरकार ने पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इको-सिस्टम के विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस)
- बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना
- आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना
- इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालकों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने की योजना (एसपीईसीईएस)
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी और ईएमसी 2.0) योजना
- सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम
- संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस)
- सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017

- कराधान में सुधार, जिसमें शुल्क संरचना का युक्तिकरण, पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट आदि शामिल हैं।
- लागू कानूनों/विनियमों के अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देना।

इन पहलों के परिणामस्वरूप, पिछले 11 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का विस्तार हुआ है जिसे निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है:

| #  | 2014-15         | 2024-25         | टिप्पणी            |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उत्पादन (रु.)* | ~1.9 लाख करोड़  | ~11.3 लाख करोड़ | 6 गुना वृद्धि हुई  |
| मोबाइल फोन का उत्पादन (रु.)*             | ~0.18 लाख करोड़ | ~5.5 लाख करोड़  | 28 गुना वृद्धि हुई |

\*उद्योग के अनुमानों के अनुसार

विशेष रूप से मोबाइल फोन, ईएमएस, पुर्जे, परीक्षण, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और सहायक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में विनिर्माण क्षेत्र स्वाभाविक रूप से श्रम-प्रधान है। इन योजनाओं के तहत नई विनिर्माण लाइनें, आपूर्तिकर्ता इको-सिस्टम और औद्योगिक क्लस्टर स्थापित होने से, शॉप-फ्लोर श्रमिकों, तकनीशियनों, इंजीनियरों, गुणवत्ता विशेषज्ञों और आपूर्ति श्रृंखला कर्मियों के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स, अनुरक्षण, डिजाइन और अनुपालन जैसी सेवाओं में भी नौकरियों की मांग बढ़ी है। उद्योग के आकलनों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र ने देश में लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं।

ख) भारत सरकार की पहलें प्रकृति में अखिल भारतीय स्तर की हैं। विनिर्माण इकाइयों के स्थान का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित सहायक नीति और व्यापार सुगमता के अन्य उपायों को ध्यान में रखते हुए उद्योग द्वारा किया जाता है।

(ग) भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन और भारत से निर्यात भारत में पंजीकृत कंपनियों द्वारा किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार का 75% से अधिक हिस्सा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के माध्यम से होता है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में घरेलू स्रोतों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न घटकों का आयात भी शामिल है, जो प्रतिस्पर्धी लाभ, इन्टर्मीडीएरीज के लिए कच्चे माल, पुर्जों की उपलब्धता, अथवा कीमत या प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। सरकार समय-समय पर देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की स्थिति की समीक्षा करती है और आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने के लिए घरेलू क्षमता और सामर्थ्य को बढ़ाने हेतु आवश्यक नीतियां लागू करती है।

(घ): सरकार के पास रोजगार एवं क्षमता सृजन सहित उत्पादन, निर्यात, निवेश संबंधी प्रतिबद्धताओं और योजना-वार परिणामों की सुदृढ़ निगरानी एवं रिपोर्टिंग तंत्र मौजूद हैं। संबंधित मंत्रालय और कार्यान्वयन एजेंसियां समय-समय पर कार्य-निष्पादन संकेतकों की समीक्षा करती हैं और प्रगति का आकलन करने तथा कमियों की पहचान करने के लिए उद्योग जगत के हितधारकों से परामर्श करती हैं। सरकार इन निगरानी प्रणालियों को निरंतर सुदृढ़ करती है ताकि विनिर्माण एवं निर्यात में वृद्धि से रोजगार, कौशल विकास और घरेलू उद्योग के विकास को ठोस लाभ सुनिश्चित हो सके।

\*\*\*\*\*